

संपादकीय

बयानबाजी से बाज आयें बड़बोले नेता

*भारतीय राजनीति के गलियारों में चिंता व
चिन्तन होने लगा है कि राजनीतिक दल अपने नेताओं
को केवल चुनाव जिताने वाली मशीनें न समझें,
बल्कि उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारी, नेता अपनी भाषा
की मर्यादा और सामाजिक समरता व संतुलन का
पाठ पढ़ाएं*

चुनाव आयोग को भी ऐसे बयानों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कठोर निर्देश और दंड का प्रावधान करना चाहिए ताकि यह संदेश स्पष्ट हो जाए कि कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है ऐसे बयान बाज बड़बोले नेता से बिगड़ बोल से जनता भारी आक्रोश व्याप्त है

सम्पूर्ण विश्व का ध्यान इन दिनों भारत पर टिकी हुई है। विशेषकर अन्तराष्ट्रीय राजनीति विशेलज्जनों का, विगत दिनों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक युद्ध से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी। जिसमें हमारी पराक्रमी सेनाओं ने आतंकी के आकाओं पाकिस्तान के सरजर्मी में घुस कर उनके ठिकानों जर्मांदोष कर दिया है। जिसके बाद हमारे सेनाओं व देश - विदेशों में की जय जयकार हो रही थी, तभी मध्य प्रदेश के एक बड़े बोले भाजपा के कैबिनेट मंत्री ने एक जन सभा में गैर जिम्मेदार व्यान बाजी का बेसुरा राग अलाप दिया। यह मामला मध्य प्रदेश के उच्च न्यायलय में पहुँच गया परिणाम की गंभीरता को भापते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने दिया।

उच्च न्यायलय ने पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया कि आज शाम 6 बजे तक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर न्यायालय की अवमानना ??अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी वही मंत्री के वकील ने तर्क दिया कि अदालत का आदेश पूरी तरह से अखबारों की रिपोर्टों पर आधारित था। अदालत ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस)की धारा 196, जो धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने वाले भाषणों या कार्यों को दंडित करती है, इस मामले में प्रथम दृष्टया लागू होती है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को उस समय राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राज्य के आदिवासी मामलों के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंटूर पर मीडिया को जानकारी देने वाली दो महिला सैन्य अधिकारियों में से एक कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में टिप्पणी की। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी को झशर्मनाक और अश्लील झक्क कहा। विपक्ष की ओर से व्यापक निंदा और अपनी ही पार्टी के भीतर आलोचना के बाद उन्होंने मंगलवार को माफ़ी मांगी।

भारत की वॉटर स्ट्राइक से बिलबिलाने लगा पाकिस्तान

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पोषित और प्रेषित आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों का धर्म पूछकर नृशंस हत्या की। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने जहां पाकिस्तान को सैन्य मोर्चे पर तबाह कर दिया वहाँ, उससे पहले सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले से पानी की एक-एक बूँद के लिए तरसा दिया है। भारत ने सिंधु जल संधि को ऐसे समय में निर्लंबित किया है जब पाकिस्तान पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के सिंधू और पंजाब प्रांत में छह नई नहरें बनाने की योजना भी विवादों में फंसी है। इतिहास के आलोक में अगर बात की जाए तो सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करने को लेकर नौ साल तक वार्ता चली और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अय्यूब खान के मध्य 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची में समझौता हुआ।

इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को आर्वाणित किया गया। वहाँ तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, ज़ेलम और चिनाब के जल का 80 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान को आर्वाणित किया गया। समझौते में जिस तरह से जल का बट्टवारा किया गया उससे तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री और सरकार की रीति—नीति का समझा जा सकता है। पीएम नेहरू ने देशहित की बजाय पाकिस्तान के हितों का अधिक ध्यान रखा। यह संधि पाकिस्तान में कृषि और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम है और पाकिस्तान में 80 प्रतिशत सिंचाई के पानी की आपूर्ति इन्हीं नदियों के पानी से होती है। कई शहरों के लिए पेयजल की आपूर्ति भी इस नदी

से की जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पहले हुई इस जल संधि के तहत दोनों देशों के बीच नदियों के जल प्रबंधन को लेकर समझौता हुआ था। नदियों को बांटने का ये समझौता कई युद्धों, मतभेदों और झगड़ों के बावजूद 65 वर्षों से अपने स्थान पर यथावत रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों के मारे जाने के बाद भारत ने जिन कड़े कदमों की घोषणा की उनमें यह सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। भारत द्वारा संधि को निलंबित करना इसकी स्थापना के बाद से पहली बार है, जो सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी जल कूटनीति में बदलाव का संकेत है। यह भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है।

2016 में उरी में भारतीय सेना के एक शिविर पर हमले के बाद डेढ़ सप्ताह बाद हुई एक समीक्षा बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का इशारा सिंधु जल समझौते की ही ओर था। 2019 में पुलवामा में सुरक्षाबलों पर हमले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान देते हुए कहा था, सरकार ने पाकिस्तान को पानी के वितरण को रोकने का फैसला किया है। अगस्त 2019 में भारत के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था, सिंधु जल संधि का उल्लंघन किए बिना पाकिस्तान को जाने वाले पानी को रोकने के लिए काम शुरू हो गया है।

भारतीय सेना से करारी शिक्षत के बाद पाकिस्तान अब पानी को लेकर भारत के सामने गिर्ड़िगिड़ाने लगा है। पाकिस्तान की सरकार ने 14 मई को भारत के जल शक्ति मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। वहीं, एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि पाकिस्तान की



ये अपील तब की गई जब भारत चिनाब नदी पर बगलिहार और सलाल जलविद्युत परियोजनाओं में प्रलशिंग और डिसिल्टिंग का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव सम्मिलित अली मुर्तजा ने भारत को लिखी चिट्ठी में कहा, सिंधु जल समझौता स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में खरीफ की फसल के लिए पानी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने 13 मई को कहा कि अगर भारत सिंधु जल संधि को फिर से शुरू नहीं करता है और हमारी तरफ आने वाले पानी को मोड़ने की कोशिश करता है तो दोनों देशों के बीच लागू हुआ संघर्ष विराम खतरे में पड़ सकता है।

सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की ये पेशकश उसकी छतपटाहट को साफ दिखा रही है। यह पहली बार नहीं था जब भारत सरकार ने 1960 में दोनों देशों के बीच हुई इस संधि में बदलाव की मांग की थी। दो साल पहले भारत ने

A photograph of a large dam, likely the Chenab Dam in India, showing a massive amount of water gushing out from its gates, creating a large plume of white spray. The dam is built into a rocky hillside, and a steep, forested mountain slope is visible to the right.

پاکستان کو اس سंبندھ میں نوٹیس بھا جا ثا لئکن اس نوٹیس میں سرچ بدلاؤں کے بارے میں بات کی گई تھی । ہالائیک اگسٹ 2024 میں بھجے نوٹیس میں بھارت نے بدلاؤں کے ساتھ-ساتھ سامانڈوتے کی %سماں کا % کرنے کی بھی بات کی تھی । اس میں سیما پار سے آتکنکا دی گاتی ویڈیو % کا بھی علیحدہ کیا گयا تھا । اس میں بھی بھارت کی اور سے کہا گیا تھا کہ %سیما پار سے آتکنکا دی اس سامانڈوتے کے سुچارا رूپ سے سانچالن میں بادھا ہے । لئکن پاکستان نے اس پر کوئی عتیر نہیں دیا، اب جبکہ بھارت نے سامانڈوتے کو س्थगیت کر دیا ہے تو پاکستان بھونٹنے پر آ گیا ہے ।

15 مئی کو اک کار्यک्रम میں سانچا ددا تا اؤں نے

विदेश मंत्री एस. जयशंकर से जब सिंधु जल समझौते को लेकर प्रश्न किया, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह समझौता अभी निरस्त ही रहेगा। भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं है और इस मामले में पाकिस्तान के साथ बातचीत

नहीं होगी। विदेश मंत्री के ताजा बयान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कर चुके हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं सिंधु जल संधि के निलंबन से पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि इसकी 80 प्रतिशत कृषि भूमि इन नदियों पर निर्भर है। इस व्यवधान से खाद्य सुरक्षा, नागरीय जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा साथ ही पाकिस्तान के सकल धरेलू उत्पाद में सिंधु नदी तंत्र के 25 प्रतिशत योगदान के कारण आर्थिक अस्थिरता भी उत्पन्न होगी। नदी प्रवाह डेटा को रोकने की भारत की क्षमता से पाकिस्तान की सुभेद्या और बढ़ जाएगी तथा बाढ़ तपतरा और जल संसाधन प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होगी। भावार्थ यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में जल संकट से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याएं बढ़ना तय है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में जल बंटवारे को लेकर पुराना विवाद है। वर्तमान जल संकट ये विवाद और गहराएगा।

नारा जब अपने हस्त का ताना नादेवा रोपा, ब्यास और सतलुज के जल को अपने लिए प्रयोग करने की योजना बना रहा है। इस पर तुरंत काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं को भी आंतिम रूप दिया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के इन कदमों से पाकिस्तान को लंबे समय में नुकसान पहुँचना अवश्यम्भावी है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो टेरेजिम पर होगी ज पाकिस्तान से बात होगी..तो पीओके पर होगी। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो आतंकवादियों का साथ देगा या फिर अपने प्यासे खेतों और नागरिकों की प्यास बुझाने के लिये शांति और शालीनता के मार्ग का चुनाव करेगा।

